दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित निर्णय :11 जनवरी, 2023
आदेश उद्घोषित :12 जनवरी, 2023

\+ सि.वा.(मू.प.) 20/2023 में अं.आ. 507/2023

सुशील अंसल .....वादी

द्वारा: श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सह गौतम खजानची, श्री कुमार वैभव, सुश्री सोमाया गुप्ता और सुश्री सुकन्या जोशी, अधिवक्तागण

बनाम

एंडेमोल भारत प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य .....प्रतिवादीगण

द्वारा: श्री संदीप सेठी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री निधीश मेहरोत्रा, सुश्री अनुश्री रौता, श्री राहुल धोटे, श्री एस. एस. अहलूवालिया, सुश्री देवांगिनी राय, श्री मोहित बांगवाल,

सुश्री नारायणी पी. चौधरी, प्रति.-1 के अधिवक्ता

श्री निधिश मेहरोत्रा, सुश्री अनुश्री रौता, श्री राहुल धोटे, श्री एस. एस. अहलूवालिया, सुश्री देवांगिनी राय, श्री मोहित बांगवाल, सुश्री नारायणी पी. चौधरी, प्रति.-2 के अधिवक्ता

श्री राजीव नायर और श्री अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ श्री मानव कुमार, श्री एस. देबरथा रेड्डी, सुश्री शिवांगी शर्मा, श्री सौरभ सेठ, सुश्री मंजुला दास, श्री विनय त्रिपाठी, श्री ऋषभ शर्मा, श्री दर्पण सचदेवा और श्री अभिषेक ग्रोवर, डी-3 के अधिवक्ता

श्री विकास पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रावी शर्मा, सुश्री मनीषा जैन, डी-4 और 5 के अधिवक्ता

सुश्री वृंदा भंडारी, सुश्री नताशा माहेश्वरी, श्री माधव अग्रवाल, डी-6 के अधिवक्ता

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा

<u>आदेश</u>

1. वर्तमान मुकदमा प्रतिवादी सं. 3 को 'ट्रायल बाई फायर' नामक नाटक की डिजिटल/ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रदर्शन, प्रसारण और रिलीज से रोकने के लिए अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने के लिए संस्थित किया गया है। यह वेब सीरीज 13 जनवरी, 2023 को प्रसारित की जानी है। इसके अतिरिक्त वादी प्रतिवादी के द्वारा **'ट्रायल बाई फायर: दा ट्रैजिक टेल ऑफ़ उपहार फायर ट्रेजेडी'** नामक पुस्तक के प्रकाशन, जिसमें कि पुस्तक का ऑडियो/वीडियो रूपांतरण और डिजिटल/ओटीटी प्लेटफार्मों पर पुस्तक के माध्यम से किए गए अपमानजनक, निंदात्मक और झूठे बयानों का प्रदर्शन, प्रसारण और टीवी प्रसारण के खिलाफ अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री की मांग करते हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिवादियों के विरुद्ध डिलीवरी-अप की राहत की भी मांग की गई है ।

2. न्यायालय ने वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित श्री सेठी, प्रश्नगत वेब श्रृंखला के निर्माता और सह-निर्माता श्री नायर और श्री सिब्बल, प्रतिवादी सं. 3 की ओर से उपस्थित फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पाहवा, प्रतिवादी सं. 4 एवं

5 के लिए उपस्थित फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता, पुस्तक के लेखक एवं प्रतिवादी सं. 6 के लिए उपस्थित सुश्री भंडारी, जिन्होंने पुस्तक प्रकाशित की थी, को सुना है।

3. पक्षकारों ने अंतरिम व्यादेश के लिए इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई प्रस्तुतियों को सम्बोधित किया है और जिसके संदर्भ में प्रधान मुकदमा में की गई प्रार्थनाओं के समान दावा अंतरिम व्यादेश राहत के रूप में किया गया है। जिन प्रस्तुतियों को सम्बोधित किया गया है, उनको समझने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तथ्यों पर ध्यान देना उचित होगा।

4. 13 जून, 1997 को नई दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित उपहार सिनेमा में आग लग गई थी। उक्त घटना में 59 निर्दोष लोगों के मारे जाने की बात सामने आई थी। उस घटना के संबंध में जांच 23 जुलाई 1997 को केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित कर दी गई। उपरोक्त के अतिरिक्त, सबूतों से छेड़छाड़ से संबंधित आरोपों के संबंध में वादी एवं अन्य नामित अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी सं. 207/2006 भी दर्ज की गई है। 20 नवंबर 2007 को, सक्षम न्यायालय ने सत्र केस सं.13/2007 [एतद् पश्चात संक्षिप्तता के लिए **"मुख्य उपहार मामला"** कहा जाएगा] में निर्णय पारित किया था जिसमें वादी को धारा 304 अ के साथ सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 14 के साथ-साथ सह-पठित **भारतीय दंड संहिता 1860**[2] की धारा 337 और 338 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। वादी को दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5,000/- रुपये

के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। कहा जाता है कि वादी ने दोषसिद्धि के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर की थी, जिसका निपटान इस न्यायालय ने 19 दिसंबर 2008 के आदेश में दोषसिद्धि को मानते हुए एवं दी गई सज़ा को कम करके एक साल का करते हुए 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ किया था।

5. वादी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 597/2010 के माध्यम से पूर्वोक्त निर्णय पर सवाल उठाया है। उच्चतम न्यायालय ने कथित अपील पर वादी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। हालांकि, खंडपीठ के फ़ाज़िल न्यायाधीशों ने सजा के मुद्दे पर अलग राय व्यक्त की है। परिणामस्वरुप, यह मामला उच्चतम न्यायालय के तीन फ़ाज़िल न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया। 22 सितंबर, 2015 को उच्चतम न्यायालय ने वादी को दी गई सजा को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया और एक वर्ष अतिरिक्त कारावास के बदले में 30 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का विकल्प दिया। यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि जुर्माना वादी द्वारा अदा किया जाता है, तो सजा पहले से ही कारावास में बिताई गई अवधि तक कम हो जाएगी। उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ ने उन समीक्षा याचिकाओं को प्राथमिकता दी जो 9 फरवरी 2017 को खारिज कर दी गई थी।

6. जहां तक साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले का संबंध है, विचारण न्यायाधीश ने 08 अक्टूबर, 2021 के अपने निर्णय में वादी को भा.दं.सं. की धारा 120बी के साथ सह-पठित धारा 409, धारा 120बी और धारा 201 के तहत दोषी ठहराया था। वादी द्वारा उपरोक्त अपराधों में सात साल की सामान्य हिरासत की सज़ा सुनाई गई थी, और इसके अतिरिक्त उसे 2.25 करोड़ के जुर्माने का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। निर्विवाद रूप से, वादी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जो कि 18/19 जुलाई, 2022 में अपील न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को कायम रखते हुए, वादी की हिरासत की सज़ा को 3 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के भुगतान के बदले बिताई गई हिरासत की अवधि तक कम करते हुए खारिज़ कर दी थी। निर्विवाद रूप से, लगाए गए इस जुर्माने के भुगतान से वादी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ ने अपील न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है जो वर्तमान में विचाराधीन है। वादी ने एक पुनरीक्षण याचिका भी प्रस्तुत की है जो कि इस न्यायालय के बोर्ड में लंबित है।

7. कहा गया है कि 4 जनवरी 2023 को वेब सीरीज “ट्रायल बाय फायर” का एक आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया था। यह भी कहा गया है कि कथित दावा प्रतिवादी सं. 4 और 5 द्वारा लिखित पुस्तक पर और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वादी ने मुकदमे में दावा किया है कि उसके परिचित उसके पास पहुंचे और उनके अनुसार आक्षेपित सीरीज के ट्रेलर से वादी के लिए उनका

सम्मान कम हो जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी दावा किया गया है कि यह पता लगने पर कि आक्षेपित सीरीज प्रतिवादी सं. 4 और 5 द्वारा लिखित पुस्तक की अंतर्निहित वस्तु पर आधारित थी, उन्होंने इसकी एक प्रति 08 जनवरी 2023 को खरीदी और उसे पढ़ने से उनको पता चला कि यह झूठे और अपमानजनक बयानों से भरी हुई थी। ये तथ्य और दावे वाद के अनुच्छेद 81 को पढ़ने से स्पष्ट हैं। अनुच्छेद 81 में वादी दावा करता है कि उपरोक्त घटनाएं प्रतिष्ठा, अपमान, कलंक और अपूरणीय क्षति का हेतुक बन रही हैं और आगे भी बनेंगी। यह भी कहा गया है कि यदि वेब सीरीज प्रकाशित की जाती है, तो इसका पुनरीक्षण याचिकाओं के परिणामों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले से उत्पन्न हुई हैं। वाद के अनुच्छेद 26 में, वादी यह दावा करता है कि :

> "26. अभिलेख के अनुसार यह सीरीज कथित रूप से आक्षेपित पुस्तक पर आधारित है। यह कहा गया है कि इस पुस्तक का प्रकाशन और विमोचन 2016 में किया गया था, यानी उस समय जब मुख्य उपहार मामले में पुनर्विचार याचिकाएं भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थी। वादी को आक्षेपित पुस्तक की सामग्री या लेखकों द्वारा प्रस्तुत घटनाओं के स्वर, भाव और संस्करण के बारे में जानकारी नहीं थी, और उसके पास इसे पढ़ने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि वादी का सारा समय और संसाधन लंबित कानूनी कार्यवाहियों और उनके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए समर्पित था।"

8. वादी के विरुद्ध और पुस्तक में दिए गए बयानों का उल्लेख करते हुए, यह दावा किया जाता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना के एकतरफे वर्णन पर आधारित है और यह पूरी पुस्तक अतिशयोक्ति, अतिशयोक्तिपूर्ण बयानों पर आधारित है जो वादी के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिकूल है। यह भी कहा गया है कि जब वादी को अंततः भा.दं.सं. की धारा 304अ के संदर्भ में लापरवाही से मौत का कारण बनने के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, पुस्तक में विभिन्न मानहानिकारक बयान हैं, जिनमें वादी का हत्यारा और खूनी होने जैसे आरोप शामिल हैं। वादी के अनुसार, एक सीरीज़ जो कि पुस्तक पर आधारित है, आवश्यक रूप से वादी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय नुकसान पहुंचाने के अलावा उसके निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन करेगी।

9. वादी की ओर से पेश फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने पुस्तक के कुछ उदाहरणों को बताते हुए यह तर्क दिया था कि क्योंकि इसमें वादी के विरुद्ध अपमानजनक बयान और आरोप शामिल हैं, यह स्पष्ट है कि वेब सीरीज एक समान अवधि का पालन करेगी और इस प्रकार वादी द्वारा लगाए गए मानहानि के आरोप को स्पष्ट रूप से स्थापित करेगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि जिस तरह से पुस्तक में पूरी घटना को चित्रित किया गया है वह स्पष्ट रूप से उन तथ्यों के विपरीत है जो मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए हैं और यह कि इसकी अंतर्वस्तु के पठन से यह पता लगता है कि वे समवर्ती निष्कर्षों की विपरीत हैं जो कि आपराधिक मुकदमे के दौरान वादी के सम्बन्ध में पाए गए थे। श्री अग्रवाल ने

इस तथ्य पर जोर दिया है कि सीरीज के ट्रेलर को पहले ही लगभग 1.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और इसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है। फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि दृश्य माध्यम की पहुंच और प्रभाव को हमेशा लिखित कार्य की तुलना में कहीं अधिक माना गया है। श्री अग्रवाल के अनुसार न्यायालय को आवश्यक रूप से उस अपरिवर्तनीय नुकसान और प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए जो कि वेब सीरीज द्वारा वादी पर पड़ा है। इसलिए यह आग्रह किया गया कि एक तत्काल और पूर्व-प्रसारण निषेधाज्ञा स्पष्ट रूप से आवश्यक है।

10. प्रतिवादी संख्या 3 के आधिकारिक वेब पेज पर दिखाई देने वाली सीरीज के विवरण का उल्लेख करते हुए, श्री अग्रवाल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि "25 साल लंबी लड़ाई" का संदर्भ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वेब सीरीज से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ के मामले पर नकारात्मक एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस संदर्भ में यह कहा गया कि आक्षेपित सीरीज की स्ट्रीमिंग न केवल वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाएगी, बल्कि लंबित पुनरीक्षण याचिका में उसके मामले पर अनुचित रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

11. प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री नायर और श्री सिब्बल ने फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कहा है कि यह तथ्य कि इस वेब सीरीज का प्रसारण 13 जनवरी, 2023 को होना है, का प्रचारण विधिवत रूप से 18 दिसंबर, 2019 को किया

गया। फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियां और लेख जो प्रासंगिक समय पर प्रस्तुत किए गए थे और प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा लिखित पुस्तक के आधार पर वेब सीरिज़ के निर्माण की ओर संकेत करते हैं, को न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया है इस संबंध में श्री नायर ने प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न लेखों का भी उल्लेख किया था। यह भी बताया गया कि वादी का मुकदमा और दोषसिद्धि एक तथ्य था जो आपराधिक कार्यवाही के दौरान विभिन्न समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया था। यह भी कहा गया है कि यह तथ्य कि उच्चतम न्यायालय ने अंततः वादी एवं अन्य दोषियों को पहले से गुजारी गई अवधि के अतिरिक्त कोई जेल की सजा नहीं दी थी और केवल जुर्माना लगाया था, व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए थे और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे। फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता भी न्यायालय का ध्यान उन सभी लेखों की तरफ लेकर गए हैं जो की प्रमुख समाचार पत्रों में छपे हैं जिनमें साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ के मामले में वादी की दोषसिद्धि की जानकारी दी गई थी। यह समाचार पत्र लेख नवंबर 2021 में बहुत पहले प्रकाशित हुए थे। तब यह बताया गया था कि प्रतिवादी सं 3 ने 14 दिसंबर 2022 को ही विवादास्पद वेब सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 13 जनवरी 2023 से प्रसारित करने के अपने इरादे का खुलासा किया था। प्रतिवादी संख्या 3 की उपरोक्त घोषणा भी प्रमुख समाचार पत्रों में रिपोर्ट की गई थी। सारांश में यह कहा गया कि अंतिम समय में न्यायालय को संपर्क करने के कारण वादी अंतरिम व्यादेश का हकदार

नहीं था। फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले अस्वीकरण का सन्दर्भ लिया है और निवेदन किया है कि यह स्पष्ट है कि यह वेब सीरीज प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर आधारित थी और क्योंकि यह पुस्तक एक काल्पनिक कृति थी, इसकी किसी पात्र से समानता पूर्ण रूप से आकस्मिक एवं संयोगवश है। जिस अस्वीकरण को न्यायालय के समक्ष रखा गया था वह इस प्रकार है :

> "यह श्रृंखला एक काल्पनिक कृति है, जो कि नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित "ट्रायल बाय फायर: द ट्रेजिक टेल ऑफ द उपहार फायर ट्रेजेडी" नामक पुस्तक से प्रेरित है, जो कि 2016 में प्रकाशित की गई थी।
>
> इस सीरीज के कुछ पात्र, स्थान, नाम और घटनाएं काल्पनिक हैं और इन्हें नाटकीयकरण के उद्देश्य से सृजनात्मक रूप से परिकल्पित किया गया है। सीरीज दर्शाई गई किसी घटना, वृत्तांत की सत्यता या यथार्थता का कोई दावा नहीं करती है। सीरीज के पात्रों, स्थानों, नामों और घटनाओं का किसी भी वास्तविक घटना, वस्तु, स्थान या व्यक्ति (जीवित या मृत) के साथ कोई समानता या समरूपता पूर्ण रूप प्रासंगिक और आकस्मिक है।"

12. प्रतिवादी सं. 3 की ओर से यह तर्क दिया गया था कि प्रकाशन पूर्व व्यादेश पर केवल अपवादात्मक स्थितियों में विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए उच्च स्तर की तैयारी की जानी चाहिए। इसके लिए इस मामले में **खुशवंत सिंह और अन्य बनाम मेनका गांधी** में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय

को आधार बनाया गया था। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश को यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है :

> "59. पहले यह उचित होगा कि प्रतिवादी द्वारा वाद में दिए गए हिस्सों को अपमानजनक और मानहानिकारक माना जाए। प्रतिवादी के फ़ाज़िल अधिवक्ता की ओर से हमारे समक्ष यह विवाद नहीं रखा गया है कि जैसा कि चार्ट में उल्लिखित है, जिन तीन अनुच्छेदों की शिकायत की गई है उनके अलावा, अन्य पर पहले से ही टिप्पणी की जा चुकी थी और पिछली पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रकाशित की गई थी । हमने प्रतिवादी के फ़ाज़िल अधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर विचार किया है कि विषय वस्तु को व्यक्त करने के लिए भाषा पहले प्रकाशित की गई भाषा के मुकाबले अलग अर्थ देती है। हम प्रतिवादी के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत कथित निवेदन से सहमत नहीं हैं। यदि शिकायत के अनुच्छेदों और इंडिया टुडे के 15 अप्रैल, 1982, 30 अप्रैल, 1982 के प्रकाशन एवं पुपुल जयकर और वेद मेहता की पुस्तक की तुलना की जाए, तो शब्द भले ही एक से न हों, लेकिन जिस अवधारणा और अर्थ को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है, वह लगभग एक ही है । जहाँ तक अन्य तीन अनुच्छेदों का संबंध है, लेखक ने या तो अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर या स्वयं अपने विचारों और टिप्पणियों के आधार पर वक्तव्यों को स्वीकार किया है। इसलिए विचारणीय प्रश्न इन प्रकाशनों के संबंध में प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे के सम्बन्ध में ऐसे पूर्व प्रकाशनों के प्रभाव का है । अपीलार्थियों के फ़ाज़िल अधिवक्ता की प्रस्तुति में बल है कि न केवल राष्ट्र के तत्कालीन राज परिवार से संबंधित पहलुओं के बारे में व्यापक प्रचार किया गया था, बल्कि प्रतिवादी ने संभवतः अपनी स्वर्गवासी सास द्वारा किए गए अन्याय के विरुद्ध अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया को आधार बनाया था। इस प्रकार जिस विवाद पर टिप्पणी की जा रही है वह वास्तव में सदन की चार दीवारों तक ही नहीं, बल्कि विवाद के संबंध में किए जा रहे सर्वेक्षण की सीमा तक फैले व्यापक प्रचार और टिप्पणियों द्वारा प्राप्त की गई है। उस समय कोई

शिकायत नहीं थी। यह बार-बार दिए गए अपमानजनक बयानों को रोकने का मामला नहीं है, जैसा कि प्रतिवादी के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा कहा गया है। प्रतिवादी के फ़ाज़िल अधिवक्ता ने (उपरोक्त) हरिशंकर मामले में मध्य प्रदेश न्यायालय पर और (उपरोक्त) के वी रमन्नैया मामले में आंध्र प्रदेश न्यायालय पर विश्वास रखा है। विवाद प्रतिवादी और उसकी स्वर्गवासी सास, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के बीच के मुद्दों तक सीमित है। प्रतिवादी ने अपने विवाद को प्रेस में रिपोर्ट करने के बारे में कोई राय ज़ाहिर नहीं की है। प्रश्नगत विवाद का स्वरूप अपीलकर्ता सं. 1 द्वारा अपनी आत्मकथा में प्रकाशित कराए जाने का था और इसलिए प्रत्यर्थी अभी प्रकाशित किये जाने वाले विषयवस्तु की शिकायत नहीं कर सकता है ताकि उसके प्रकाशन को रोका जा सके। प्रत्यर्थी की चुप्पी एवं उसके द्वारा पूर्व प्रकाशन के विरुद्ध शिकायत से प्रथम दृष्टया मामला उसकी चुप्पी या कम से कम विषयवस्तु के प्रकाशन इस प्रकार हरिशंकर के मामले में (उपरोक्त) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर और के. वी. रामानैया के मामले में (ऊपर) आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रतिवादी का वकील गलत है। प्रश्नगत विवाद प्रतिवादी और उसकी दिवंगत सास, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच विवादों से संबंधित था।प्रतिवादी ने प्रेस में अपने विवादों की रिपोर्टिंग के बारे में शिकायत नहीं की।विवाद की प्रकृति कमोबेश वही थी जो अब अपीलकर्ता नं. १ द्वारा उसकी आत्मकथा में प्रकाशित किए जाने की मांग की गई है और इस प्रकार प्रतिवादी अब प्रकाशित किए जा रहे उसी मामले की शिकायत नहीं कर सकता है ताकि प्रकाशन को रोका जा सके | पूर्व प्रकाशन के खिलाफ प्रतिवादी और उसके द्वारा शिकायत न करने का मौन प्रथमदृष्टया सामग्री के प्रकाशन के संबंध में उसकी स्वीकृति या कम से कम शिकायतों की कमी के बराबर है.यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलकर्ता के खिलाफ नुकसान का उपचार अभी भी प्रतिवादी का संबंध है।

60. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में प्रतिष्ठापित प्रकाशन का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता पावन है।इस अधिकार का किसी व्यक्ति या

राज्य द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।प्रतिबंध के केवल मानदंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उपबंधित हैं।इस पुस्तक का पूरा विषय अभी प्रकाशित होना बाकी है, जिसमें संबंधित अध्याय भी शामिल है।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश प्रकाशन पूर्व व्यादेश है।विषय वस्तु की सामग्री पहले ही रिपोर्ट की जा चुकी थी और लेखक उसी पर कायम है।इसे ध्यान में रखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि प्रतिवादी कोई शिकायत नहीं कर सकता है जिससे कि स्वयं प्रकाशन को रोका जा सके जब उसे नुकसानी के रूप में उपचार उपलब्ध हो।हम मानहानि की कसौटी पर अपीलकर्ता नं. 1 के बयानों की जांच नहीं कर रहे हैं| इस स्तर पर हमारे लिए ऐसा करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम जो देखते हैं वह यह है कि बयान इस तरह की प्रकृति के नहीं हैं कि सामग्री के प्रकाशन से भी निषेधाज्ञा मंजूर की जाए, जब अपीलकर्ता किसी मामले में मुकदमे में परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं।

61. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्व प्रकाशन में विवाद के मामले की रिपोर्टिंग उन्हें सार्वजनिक दस्तावेज नहीं बनाती है जैसा कि फूलन देवी के मामले में (उपरोक्त) इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।हालांकि, सवाल यह नहीं है कि दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज हैं, लेकिन विवाद में मामले की पूर्व रिपोर्टिंग होने और इस पर टिप्पणी करने के संदर्भ में विषय वस्तु सार्वजनिक डोमेन के दायरे में है। वही है। इस प्रक्रम पर इस न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा दिए विद्वान फूलन देवी के मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय पर विचार करना उपयोगी हो सकता है।फैसले के सावधानीपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मामला अजीब था क्योंकि यह एक महिला के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दावे से संबंधित था यदि संबंधित महिला जीवित थी और वह नहीं चाहती थी कि इसे सार्वजनिक किया जाए। यह उन परिस्थितियों में था कि आदेश पारित किया गया था, हालांकि हम यह जोड़ सकते हैं कि बाद में एक स्पष्ट समझौते पर उसे सार्वजनिक कर दिया गया था और उसमें वादी को आपसी समझौते के संदर्भ में मुआवजा

दिया गया था, वास्तव में विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से इस पहलू पर विचार किया और कहा कि नग्न, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की परेड के प्रदर्शन और ग्राफिक विवरण न केवल भावनाओं को आहत करता है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा को विकृत करता है, व्यक्ति को बदनाम करता है बल्कि पीड़ित को भावनात्मक परित्याग की स्थिति में लाता है।

62. जांच किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण पहलू प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवारक व्यादेश की मांग करने के लिए प्रस्तुत निजता के अधिकार का दावा है।इस पहलू पर विस्तार से विचार किया गया आर. राजगोपाल के रूप में रिपोर्ट किए गए ऑटो शंकर (ऊपर) के मामले में इन पहलुओं पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की कि निजता के अधिकार के दो पहलू हैं।पहला पहलू निजता का सामान्य कानून था जिसमें निजता के गैर कानूनी अतिक्रमण से होने वाले नुकसान के लिए कठोर कार्रवाई का प्रावधान था। वर्तमान मामले में हम उसी से संबंधित नहीं हैं क्योंकि नुकसानी के मुकदमे का मुकदमा अभी चलाया जाना है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार, दूसरा पहलू निजता के अधिकार को दी गई संवैधानिक मान्यता थी जो गैरकानूनी सरकारी कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तिगत निजता की रक्षा करती है। वर्तमान मामले में यह स्थिति भी नहीं है क्योंकि हम दो नागरिकों के परस्पर अधिकारों से संबंधित हैं न कि सरकार की कार्रवाई से। पहले पहलू के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने लिखित जीवन गाथा का उदाहरण दिया था।चाहे वह प्रशंसनीय हो या अन्यथा और संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना प्रकाशित किया गया हो। प्रतिवादी श्री राज पंजवानी के विद्वान अधिवक्ता ने, अपीलकर्ता नं. १ द्वारा लिखित आत्मकथा में उसकी जीवन गाथा प्रकाशित करने के लिए प्रतिवादी की सहमति के अभाव में, इस पहलू से विचित्रता निकालने की कोशिश कि तथापि, इससे उच्चतम न्यायालय के अनुसार नुकसानी के लिए अपकृत्य की कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह वह पहलू है जो

निजता के अतिक्रमण के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए जाने वाले प्रथम पहलू से संबंधित है।

64 यह भी कहना प्रासंगिक है कि आर. राजगोपाल के मामले में उच्चतम न्यायालय (उपर्युक्त) सरकारी प्राधिकारियों द्वारा मांगी गई निवारक कार्रवाई से संबंधित था। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया।न्यूयार्क टाइम्स (पूर्वोक्त) वाले मामले में, जो पेंटागन के मामले के रूप में लोकप्रिय है, व्यक्त किए गए मताभिव्यक्तियों ने इस संबंध में सही दृष्टिकोण को संक्षेप में अधिकथित किया अर्थात् पूर्व निर्बन्धन अधिरोपित करने के लिए औचित्य दर्शित करने के लिए सरकारी प्राधिकारियों पर भारी भार है। इस प्रकार इसका उपचार नुकसान के रूप में होगा न कि संयम का आदेश।

67. हम श्री राज पंजवारी द्वारा प्रतिवादी की ओर से दिए गए इस तर्क को प्रतिग्रहण करना, प्रतिगृहीत करना, स्वीकार करना करने में असमर्थ हैं कि यदि कथन व्यक्तियों के निजी जीवन से संबंधित हैं, तो इससे अधिक कुछ नहीं कहा जाना है और सामग्री को प्रकाशित किए जाने से रोका जाना चाहिए जब तक कि वह उस व्यक्ति की सहमति के साथ न हो जिससे विषय-वस्तु संबंधित है। इस तरह की पूर्व-सेंसरशिप को हमारे संवैधानिक ढांचे की योजना में शामिल नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण में भी कुछ बल है कि मुकदमा दाखिल किए जाने से बहुत पहले प्रकाशन हुआ था, जहां वादी आवेदन करने में विलंब कर रहा है, वहां अंतवर्ती निषेधाज्ञा के लिए राहत से इनकार करने का सिद्धांत, जैसा कि अवलोकन किया गया है कि वर्तमान मामले के लिए इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र के मामले में (ऊपर) भी लागू होगा |

69. लोगों को एक विशेष विचार रखने और सार्वजनिक हित के मामले पर स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक हस्तियों का निजी जीवन भी जनहित का विषय बन जाता है। यही कारण है कि जब विवाद शुरू हुआ था तो भारत टुडे के दो संस्करणों

सहित इसका इतना व्यापक प्रचार हुआ था। जैसाकि सिल्किन बनाम बीवरब्रुक न्यूजपेपर्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) में मत व्यक्त किया गया है, सार्वजनिक जीवन के संबंध में लागू की जाने वाली कसौटी यह है कि उत्साही व्यक्ति वही कह सकता है जो वह ईमानदारी से सोचता है, उतनी ही उचित पुरुष या महिला जो जूरी में बैठती है।

70. यह उल्लेख करना दिलचस्प है कि फ्रेजर के मामले में (पूर्वोक्त) संडे टाइम्स के प्रस्तावित प्रकाशन पर विचार करते समय लार्ड डेनिंग ने ध्यान दें किया था कि संडे टाइम्स ने यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया था कि लेख वादी के लिए मानहानिकारक होगा फिर भी संडे टाइम्स ने दावा किया था कि बचाव पक्ष का दावा यह होगा कि तथ्य सत्य हैं। वर्तमान मामले में पहली दलील यह है कि बयान इस तथ्य के अलावा अपमानजनक नहीं है कि इसे प्रकाशित किया गया है और अतीत में टिप्पणी की गई है। दूसरा तर्क यह है कि अपीलकर्ता कथित बयानों की सच्चाई साबित करेंगे। लॉर्ड डेनिंग ने कहा था कि अदालतें किसी लेख के प्रकाशन को तब भी नहीं रोकेंगी जब प्रतिवादियों ने इसे उचित ठहराने या जनहित के मामले पर उचित टिप्पणी करने का इरादा व्यक्त कर दिया हो।

71. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दो प्रतिस्पर्धी हित संतुलित किए जाने चाहिए जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, एक लेखक का लिखने और प्रकाशित करने का अधिकार और निजता के आक्रमण के खिलाफ एक व्यक्ति का अधिकार और मानहानि की धमकी। हालांकि, इन अधिकारों के संतुलन को मानहानि के लिए क्षतिपूर्ति के दावे के चरण में माना जाएगा, न कि प्रकाशन के खिलाफ आदेश देने के लिए निवारक कार्रवाई।

74. यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन प्रतिष्ठापित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यवान अधिकारों को कम करना है तो समुदाय के लिए बड़े खतरे होने चाहिए। आर. रंगराजन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों (पूर्वोक्त) में, बेंजामिन

> फ्रैंकलिन को उद्धृत किया गया था जहां उन्होंने कहा था कि "लोगों की राय अलग-अलग है, दोनों पक्षों को समान रूप से जनता द्वारा सुने जाने का लाभ होना चाहिए।"

13. आगे यह प्रतिवाद किया गया कि किसी भी मामले में कोई भी निषेधाज्ञा केवल टीजर या ट्रेलर के आधार पर जारी नहीं की जा सकती है जो प्रसारित किया गया हो। यह प्रस्तुत किया गया कि जब तक वेब श्रृंखला को पूरी तरह से नहीं देखा जाता है और इसकी सामग्री के संबंध में एक आकलन किया जाता है और क्या मानहानि का मामला प्रथमदृष्टया भी बनता है, तब तक कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह भी कहा गया कि चूंकि दुर्घटना ; घटना के सभी पहलू, जो 13 जून 1997 को हुए थे, उसके बाद आपराधिक अभियोजन हुआ और अंततः वादी की दोषसिद्धि सार्वजनिक थी, इसलिए कोई निषेधाज्ञा मंजूर नहीं की जा सकती थी.विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत विद्वान कि वास्तव में जनहित वादी की आशंका से अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना भी अस्वीकार की जा सकती है। श्री नायर और श्री सिब्बल ने भी **आर. राजागोपाल बनाम तमिलनाडु[4] राज्य वाले मामले में दिखने वाले अनुच्छेद** निम्नलिखित पर भरोसा जताया |

> "**26.** इमरजेंसी अब हम उपर्युक्त चर्चा से निकलने वाले व्यापक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं:
>
> (1) निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा इस देश के नागरिकों को गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है। यह एक छद्म अधिकार है कि किसी की बात ही न सुनी जाए। एक नागरिक को

अपनी, अपने परिवार, विवाह, प्रजनन, मातृत्व, बच्चे को जन्म देने और शिक्षा सहित अन्य मामलों की निजता की रक्षा करने का अधिकार है। उनकी सहमति के बिना कोई भी उपरोक्त मामलों के बारे में कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता-चाहे वह सच हो या अन्यथा और चाहे प्रशंसनीय हो या आलोचनात्मक। यदि वह ऐसा करता है, तो वह संबंधित व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा और नुकसान के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, स्थिति भिन्न हो सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं को विवाद में धकेल देता है या स्वेच्छा से कोई विवाद आमंत्रित करता है या उठाता है।

2. पूर्वोक्त नियम अपवाद के अधीन है कि पूर्वोक्त पहलुओं से संबंधित कोई भी प्रकाशन गैर-आपत्तिजनक हो जाता है यदि ऐसा प्रकाशन न्यायालय अभिलेखों सहित सार्वजनिक अभिलेखों पर आधारित है। यही कारण है कि एक बार जब कोई मामला सार्वजनिक रिकॉर्ड का विषय बन जाता है, तो निजता का अधिकार अब अस्तित्व में नहीं रहता है और यह प्रेस और मीडिया द्वारा टिप्पणी के लिए एक वैध विषय बन जाता है।तथापि, हमारा यह मत है कि शालीनता के हित में [अनुच्छेद 19(2)] इस नियम के लिए एक अपवाद निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए।यदि कोई महिला यौन उत्पीड़न, अपहरण, अपहरण या इसी तरह के किसी अपराध की शिकार होती है तो उसके नाम का अपमान नहीं किया जाना चाहिए और घटना को प्रेस/मीडिया में प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए।

(3) उपरोक्त (1) के नियम का एक और अपवाद है-वास्तव में, यह एक अपवाद नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र नियम है।सार्वजनिक अधिकारियों के मामले में, यह स्पष्ट है, निजता का अधिकार, या उस मामले में, नुकसान के लिए कार्रवाई का उपचार उनके कार्यों और उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक आचरण के संबंध में उपलब्ध नहीं है।यहां तक कि जहां प्रकाशन उन तथ्यों और बयानों पर आधारित है जो सत्य नहीं हैं, जब तक कि अधिकारी यह स्थापित नहीं करता है कि प्रकाशन (प्रतिवादी द्वारा) सत्य के प्रति लापरवाह अनादर के साथ किया गया था।ऐसे मामले

> में, प्रतिवादी (प्रेस या मीडिया के सदस्य) के लिए यह साबित करना पर्याप्त होगा कि उसने तथ्यों की उचित जांच के बाद कार्रवाई की है, उसके लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि उसने जो लिखा है वह सही है। बेशक, जहां प्रकाशन गलत साबित होता है और दुर्भावना या व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित होता है, वहां प्रतिवादी के पास कोई बचाव नहीं होगा और वह नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि
>
> (ख) अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सुसंगत नहीं है, लोक पदधारी को वही संरक्षण प्राप्त है जो किसी अन्य नागरिक को प्राप्त है, जैसा कि ऊपर (1) और (2) में स्पष्ट किया गया है।यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि न्यायपालिका, जो न्यायालय का अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति द्वारा संरक्षित है और संसद और विधायिकाओं को उनके विशेषाधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और 104 द्वारा क्रमशः इस नियम के अपवादों का प्रतिनिधित्व करता है।

14. श्री सेठी, प्रोडक्शन हाउस की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी नं. 1 और 2 ने यहां प्रस्तुत किया कि वादी को जिम्मेदार ठहराया गया भूमिका और तथ्य जिसके कारण अंततः उनकी दोषसिद्धि हुई, वह सामग्री है जो हमेशा सार्वजनिक डोमेन में रही है और अस्तित्व में रही है और इसलिए, अंतरिम राहत प्रदान करने की प्रार्थना गलत धारणा है। सुशील अंसल बनाम राज्य 5 में अपने अंतिम निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए, श्री सेठी ने न्यायालय का ध्यान उन तीखी टिप्पणियों और निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया जो वादी के खिलाफ वापस किए गए और दर्ज किए गए थे। श्री सेठी के अनुसार, यह पूर्वोक्त निर्णय के निम्नलिखित अंशों से स्पष्ट हैः

"122. तो सवाल यह है कि क्या सिनेमा पर कब्जा करने वाले अंसल बंधुओं की लापरवाही इतनी गंभीर थी कि भा.दं.सं. की खंड 304-ए के तहत उन्हें दोषी ठहराया जा सकता था। इसके कारणों की तलाश बहुत दूर नहीं हैः

122.1. पहली बात तो यह है कि एक ऐसे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति से देखभाल की अपेक्षा की जाती है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं और यदि हजारों नहीं तो किसी अन्य स्थान की तुलना में, जहां कम लोग आते हैं या जहां सार्वजनिक कार्यों के लिए कम लोग ही आते हैं, अधिक देखभाल की जाती है। किसी स्थान पर आगंतुकों की संख्या जितनी अधिक होगी और ऐसी यात्राओं की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, उनकी सुरक्षा के लिए अधिक देखभाल की आवश्यकता होगी। यह ड्यूटी सिनेमाटोग्राफ की प्रत्येक प्रदर्शनी से शुरू होती है और तब तक जारी रहती है जब तक कि दर्शक सुरक्षित रूप से सिनेमा परिसर से बाहर नहीं निकल जाते।कि संरक्षकों को सिनेमा में प्रवेश दिया जाता है, एक मूल्य, उन्हें संविदात्मक आमंत्रित या आगंतुक बनाता है, जिनकी देखभाल करने का कर्तव्य अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। मनोरंजन की पेशकश करने वाले ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर आने वाले आगंतुकों की सुरक्षा के लिए उच्च स्तर की देखभाल की आवश्यकता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि संसद ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम और नियम बनाए हैं, जो ऐसे स्थानों पर आने वाले आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से मालिकों/कब्जा करने वालों/लाइसेंसधारकों पर विशिष्ट दायित्व पात्र योजना हैं। वार्षिक निरीक्षण और संबंधित अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता इस बात का एक और संकेत है कि कानून संरक्षकों की सुरक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानता है। अतः प्रकृति और भंग की सीमा के बारे में किसी भी प्रश्न को उपर्युक्त कर्तव्यों और दायित्वों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए जो कॉमन लॉ और वैधानिक प्रावधानों दोनों के तहत समान रूप से उत्पन्न होते हैं।

122.2. उपरोक्त पृष्ठभूमि में निर्णय देने पर यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में कब्जा करने वालों ने कानून के पत्र और कॉमन लॉ के तहत अपने संरक्षकों की सुरक्षा की देखभाल करने के अपने कर्तव्य दोनों का सम्मान नहीं किया था | कब्जा करने वालों ने न केवल स्वीकृत भवन योजना से विचलन किया, जिसने आगंतुकों की सुरक्षा के लिए खतरों को बढ़ाया, बल्कि इस प्रक्रिया में कानून की आवश्यकताओं की अवहेलना करते हुए सिनेमा का संचालन जारी रखा, जिससे दर्शकों को अपने जीवन के लिए एक उच्च स्तर

> का जोखिम उठाना पड़ा, जिसे उनमें से कुछ ने अंततः इस घटना में खो दिया। सिनेमा में आने वाले आगंतुकों की सुरक्षा की दिशा में कोई अतिरिक्त देखभाल के बजाय, अधिभोगियों ने अतिरिक्त सीटें रखने की अनुमति मांगी, जो सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ और अधिक समझौता करती हैं और दर्शकों के लिए जोखिम के स्तर को बढ़ाती हैं। एक ओर अधिभोगियों और दूसरी ओर सरकार के बीच राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुमत अतिरिक्त सीटों को हटाने के संबंध में मुकदमेबाजी का इतिहास और आग के बढ़ते खतरों के कारण अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के प्रति उनके विरोध और उनके इस आग्रह को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया कि सीटों को बढ़ाना या जारी रखना संरक्षकों की सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करेगा, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे न केवल सामान्य कानून में कर्तव्य के निर्वहन में, बल्कि डीसीआर, 1953 के प्रावधानों के तहत भी सुरक्षा के अपेक्षित मानकों को बनाए रखने के बजाय बालकनी में सिनेमा में जोड़ी गई कुछ अतिरिक्त सीटों में से थोड़ा और अधिक धन कमाने के बारे में अधिक चिंतित थे।"

15. श्री पाहवा ने लेखकों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में अंतरिम राहत के लिए की गई प्रार्थनाओं का विरोध किया। मुख्य रूप से ऊपर देखी गई प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हुए, तर्क दिया कि प्रतिवादी नं. 4 और 5 द्वारा लिखी गई पुस्तक को निश्चित रूप से 2016 में प्रकाशित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि इसकी सामग्री दो माता-पिता की धारणा पर आधारित थी, जिन्होंने इस त्रासदी में अपने किशोर बच्चों को खो दिया था और उनके अनुसार, उनके अनुसार, न्याय प्रणाली स्वयं दोषियों को पर्याप्त रूप से दंडित करने में विफल रही थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि पूर्वोक्त त्रासदी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर लेखकों का अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार, आपराधिक मुकदमे के दौरान उन्होंने जो अत्यधिक पीड़ा झेली थी, वे ऐसे मामले

थे जिन्हें स्पष्ट रूप से सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। श्री पाहवा ने प्रस्तुत किया कि वादी किसी भी मामले में व्यादेश या न्यायसंगत राहत देने का हकदार नहीं है क्योंकि मुकदमा स्वयं एक तात्विक तथ्य की छिपाव पर आधारित है, अर्थात्, वादी को 2016 में ही पुस्तक के प्रकाशन की पूरी जानकारी है। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा एक आवेदन किया गया था जिसमें वादी और एक अन्य सह-अभियुक्त को विदेश यात्रा की अनुमति देने से रोकने की मांग की गई थी, श्री पाहवा ने उक्त आवेदन के पैराग्राफ 3 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वादी देश छोड़कर भागने और अपनी संपत्तियों का निपटान करने के कगार पर था। यह बताया गया कि उपरोक्त कथन उन रिपोर्टों पर आधारित था जो तहलका पत्रिका के 15 दिसंबर 2016 के अंक में प्रकाशित की गई थीं।यह ध्यान दें करना प्रासंगिक हो जाता है कि उक्त लेख में, विशेष रूप से प्रतिवादी नं. 4 और 5 द्वारा लिखित पुस्तक का एक संदर्भ दिया गया था और कैसे पूरी कहानी उनकी राय पर आधारित थी। प्रणाली ने उन्हें हर समय बुरी तरह विफल कर दिया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री पाहवा द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वादी के लिए यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि उसने केवल 08 जनवरी 2023 को या उसके लगभग पूर्वोक्त पुस्तक का ज्ञान प्राप्त किया था।

16. प्रकाशन गृह विद्वान अधिवक्ता सुश्री भंडारी ने प्रस्तुत किया कि वादपत्र के अनुच्छेद 26 और 28 की सामग्री से यह स्पष्ट है कि वादी उस पुस्तक से पूरी तरह अवगत था जो 2016 से ही प्रसार में है। यह तर्क दिया गया कि विवादित पुस्तक को सराहा गया था एवं इस तरह से देखा जाना चाहिए था कि दोनों माता पिता के हादसे में अपने किशोर बच्चों को खो दिया था | सुश्री भंडारी के अनुसार, पुस्तक की सामग्री को विधिवत प्रकाशित और प्रसारित किया जाना ताकि जनता को उस भयावह घटना से संबंधित सभी पहलुओं का पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके जिसमें 59 निर्दोष व्यक्तियों की जान चली गई थी। सुश्री भंडारी ने उपहार सिनेमा त्रासदी और न्यायाधीश के लिए माता-पिता की अथक लड़ाई के संबंध में सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला भी अदालत के अवलोकन के लिए रखी थी। न्यायालय को ऐसे लेख भी दिखाए गए जो प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा लिखित पुस्तक की समीक्षाओं के साथ-साथ विभिन्न साक्षात्कारों को लेन्यायाधीश प्रमुख समाचार पत्रों में छपे थे, जो आयोजित किए गए थे और जिन्होंने न्याय प्राप्त न्यायाधीशने के लिए उनकी अथक लड़ाई को आगे बढ़ाया था। सुश्री भंडारी के अनुसार ये लेख इस बात के अकाट्य प्रमाण हैं कि यह पुस्तक 2016 से प्रचलन में है और इसकी विषय वस्तु और विषय वस्तु सार्वजनिक ज्ञान से संबंधित है। यह स्पष्ट रूप से विद्वान अधिवक्ता के अनुसार है वादी को किसी भी अंतरिम राहत की मंजूरी से वंचित करता है|

17. तब यह तर्क दिया गया कि केवल वही बयान जिन्हें मानहानिकारक और पुस्तक की सामग्री का हिस्सा बताया गया है, वे हैं जो वादपत्र में दिए गए हैं। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह उसका निवेदन था कि वादी को संभवतः अपने इस आरोप के समर्थन में कि उसे बदनाम किया गया था, कथित पुस्तक के किसी अन्य अंश या उद्धरणों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है| सुश्री भंडारी के अनुसार, प्रतिवादी के रूप में, प्रकाशन हाउस केवल वादपत्र में लगाए गए विभिन्न आरोपों और प्रकथनों का जवाब देने के लिए बाध्य होगा, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, एक प्रतिमुकदमाी न तो मुकदमे में दाखिल किए जा सकने वाले दस्तावेजों का जवाब देने के लिए बाध्य है और न ही उससे अपेक्षा की जाती है, सुश्री भंडारी ने तर्क दिया कि इस प्रकार मानहानि के आरोप पर केवल उन निष्कर्षों के संबंध में मुकदमा चलाया जा सकता है जो वादपत्र में दिए गए हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उन्हें संभवतः मानहानिकारक नहीं माना जा सकता है। सुश्री भंडारी ने उपरोक्त प्रस्तुति के समर्थन में **हार्वेस्ट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम बीपी सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य[6] के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया |**

प्रस्तुतीकरणः-

> “4. मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूं। जहां तक मेरी समझ का सवाल है, वाद्पत्र में वादियों द्वारा प्रतिकर का दावा किए जाने वाले निंदनीय/निंदनीय बयान की वकालत किए बिना, प्रतिवादियों के पास इसका जवाब देने का कोई अवसर नहीं है। प्रतिवादियों से अपेक्षा की जाती है कि वे वाद्पत्र में

अभिवचनों के लिए लिखित कथन प्रस्तुत करें और वाद्पत्र के साथ प्रतिवादियों पर तामील किए जाने पर भी दस्तावेजों की मांग न करें। मेरा प्रथमदृष्टया यह भी मत है कि ऐसे अभिवचन सि.प्र.सं. के आदेश 6 नियम 2 के अर्थ में एक तात्विक तथ्य होंगे और जिन्हें सि.प्र.सं. के आदेश 4 के नियम 6 के अनुसार होना आवश्यक है। यह सीपीसी के आदेश 7 नियम 1 के अर्थ में वाद हेतुक गठन करने वाला एक तथ्य भी होगा।

18. आरंभ में, उन मूल सिद्धांतों को याद करना उपयुक्त होगा जो अंतरिम व्यादेश राहत प्रदान करने को शासित करते हैं। प्रथमदृष्टया मामले के बार-बार दोहराए जाने वाले ट्रिनिटी टेस्ट, सुविधा के अतिशेष ; संतुलन और अपूरणीय क्षति के अलावा, न्यायालय इस बात पर भी विचार हेतुक के लिए बाध्य हैं कि क्या व्यादेश के जारी होने से अधिक नुकसान होगा और अन्याय कायम रहेगा, वह समय जब वादी ने पहली बार आपत्तिजनक सामग्री का ज्ञान प्राप्त किया था, क्या अभियोक्ता, यदि सहमत नहीं हुआ था, निष्क्रिय रहा था या अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सक्रिय कार्रवाई हेतुक में विफल रहा था और क्या उसने अच्छे विश्वास के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।ये पहलू अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब जो चाहा जाता है वह प्रकाशन-पूर्व या प्रसारण निषेधाज्ञा है।

19. प्रकाशन-पूर्व या प्रसारण व्यादेश को अनिवार्य रूप से उस चरण में मांगा जाएगा जब आपत्तिजनक सामग्री या तो व्यापक रूप से समीक्षा और मूल्यांकन के लिए अनुपलब्ध है या जहां यह अभिकथित किया जाता है कि अधिकारों के अतिक्रमण की गंभीर, आसन्न और तत्काल संभावना है। ऐसी स्थिति में,

निम्नलिखित कारक स्पष्ट रूप से प्राथमिक रूप से दिए जाने के हकदार होंगे-वह तत्परता जिसके साथ वादी न्यायालय में पहुंचता है, कम से कम प्रथमदृष्टया यह स्थापित करने का उसका दायित्व है कि आसन्न प्रकाशन/प्रसारण सच्चाई से पूरी तरह से अलग है, झूठ से भरा हुआ है, या व्यक्ति के लिए एक आसन्न अपमानजनक साक्ष्य है।

20. यदि न्यायालय यह पाता है कि वादी या तो तत्परता के साथ कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा है या पहले उपलब्ध होने पर अदालत में गया है यह एक ऐसी परिस्थिति होगी जो अंतरिम व्यादेश की मंजूरी के खिलाफ भारी बोझ डालेगी। इसके अलावा, यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि जिस सामग्री के प्रसारण या प्रकाशित होने की संभावना है, वह पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में मौजूद है और बिना किसी आपत्ति के काफी समय से मौजूद है, तो वह भी अंतरिम व्यादेश राहत की मांग करने के वादी के अधिकार से वंचित हो जाएगी।

21. अधिक आधारभूत धरातल पर, न्यायालय वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पहलुओं, एक ओर जनता के बीच व्यापक रूप से सूचना के प्रसार और व्यक्ति को होने वाली संभावित क्षति के बीच अतिशेष ; संतुलन कायम करने की अनिवार्यताओं पर भी विचार करेगा।उपर्युक्त संदर्भ में न्यायालयों ने प्रकाशन-पूर्व या प्रसारण निषेधाज्ञा के अनुदान के संबंध में उच्च स्तर का परीक्षण तैयार किया है। न्यायालयों ने जानबूझकर उच्च सीमा परीक्षण तैयार किया है क्योंकि व्यादेश

अनिवार्य रूप से उस चरण में मांगा जाएगा जब आपत्तिजनक सामग्री या तो मूल्यांकन और जांच के लिए उपलब्ध नहीं है या जहां प्रथमदृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचना अव्यावहारिक है कि क्या सामग्री अपमानजनक है या अपमानजनक है।उस स्तर पर न्यायालयों को अनिवार्य रूप से अप्रमाणित और अप्रमाणित आरोपों पर आधारित अपने निर्णय देने के लिए छोड़ दिया जाता है और अनिवार्य रूप से इस धारणा पर रोक लगाने के लिए कहा जाता है कि जो कुछ भी प्रकाशित या प्रसारित किया जाएगा वह अपमानजनक, निंदात्मक या मानहानि के बराबर होगा।इस तरह के कमजोर दृष्टिकोण को संभवतः तब स्वीकार नहीं किया जा सकता जब किसी न्यायालय से व्यादेश या साम्यापूर्ण राहत प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

22. उपरोक्त के आलोक में, यह अनिवार्य है कि एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पूर्व-शर्त के रूप में वादी को एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए बाध्य किया जाए। दूसरे, ऐसे वादी को यह स्थापित करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि जो प्रकाशित या प्रसारित होने वाला है वह मूल रूप से सच नहीं है, बल्कि अपमानजनक या बदनाम करने वाला है। उपरोक्त कसौटी पर खरा ना उतर पाने की स्थिति में, निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

23. जब वर्तमान मामले में उपरोक्त बुनियादी धारणाओं को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है, तो न्यायालय निम्नलिखित कारणों से वादी के पक्ष में फैसला करने में असमर्थ है

24. न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि विचाराधीन वेब सीरीज अभी प्रसारित नहीं हुई है। इसलिए इसे पूरी तरह से देखने का कोई अवसर नहीं मिला है। काल्पनिक कृति को देखने और उसकी संपूर्णता में उचित जाँच करने से पहले ही अंतरिम स्तर पर निषेधाज्ञा की राहत प्रदान करना पूरी तरह से अनुचित होगा। उपरोक्त सामग्री का अन्वेषण या जाँच के लिए उपलब्ध न होने के कारण वादी के आरोप के संबंध में प्रथम दृष्टया निष्कर्षों पर पहुँचने का प्रयास करना भी अनुचित होगा कि सीरीज में मानहानिकारक और अपमानजनक बयान हैं। न्यायालय उस अस्वीकरण को भी ध्यान में रखती है जो वेब सीरिज़ की प्रस्तावना के लिए प्रस्तावित है और जो प्रतिवादी 4 और 5 द्वारा लिखित पुस्तक से *"प्रेरित"* होने का दावा करती है |

25. इसलिए, यदि अंतरिम राहत के दावे पर पूरी तरह से पुस्तक की सामग्री के आधार पर विचार किया जाता है, तो भी वादी स्पष्ट रूप से निम्नलिखित कारणों से अंतरिम राहत का हकदार नहीं होगा। निर्विवाद रूप से प्रतिवादी 4 और 5 द्वारा लिखित काम 2016 में प्रकाशित हुआ था। यह विभिन्न समाचार पत्रों के लेखों और मीडिया रिपोर्टों से स्पष्ट है जिन्हें न्यायालय के अवलोकन के लिए रखा गया

है। वादी ने उक्त कार्य के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का विकल्प चुना, जब यह मूल रूप से 19 सितम्बर 2016 को प्रकाशित हुआ था। इन कार्यवाहियों में जो मांगी गई है, उस प्रकृति की निषेधाज्ञा की माँग करने वाले सुस्त या धीमे वादी को ऐसी राहत का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

26. निर्विवाद रूप से, 13 जून 1997 की भयावह घटना तब से सार्वजनिक बहस और चर्चा का विषय रही है। उस दिन हुई अकल्पनीय त्रासदी ने राष्ट्र का सिर शर्म से झुका दिया था। वादी का लापरवाह आचरण अच्छी तरह से प्रलेखित है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी के लिए भी दोषी ठहराया गया है, जैसा कि ऊपर दिए गए उसके फैसले के निष्कर्ष से स्पष्ट होगा। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 122 लोभ और लालच की पुनरावृत्ति है।

27. न्यायालय को इस स्तर पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस पुस्तक पर वेब सीरीज़ आधारित है, वह उन माता-पिता द्वारा लिखा गया है जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण घटना में किशोर बच्चों को खो दिया था। यह कहानी प्रणालीगत विफलता का आरोप लगाती है और जिस तरह से घटना पर मुकदमा चलाया गया, उसके खिलाफ पीड़ा प्रकट करती है। यह अनिवार्य रूप से उनके दृष्टिकोण और राय का वर्णन करती है। उनके संघर्षों और कष्टों के काल्पनिक प्रस्तुतीकरण को प्रथम दृष्टया मानहानिकारक नहीं माना जा सकता है। मौलिक रूप से, घटना के बारे में उनका व्यक्तिगत अनुभव और धारणा या वादी की दोषशीलता पूरे प्रकरण में उनका

विश्वास, छाप और समझ बनेगी। अंततः समकालीन मानकों पर सोचने वाला यथोचित रूप से सूचित व्यक्ति अपनी राय बना सकता है । किसी भी प्रकार से और प्रथम दृष्टया न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए खुद को आश्वस्त नहीं पाती है कि प्रतिवादी सं 4 और 5 द्वारा लिखी गई कहानी को पूरी तरह से काल्पनिक है या कल्पित सत्य की झलक से वंचित है।

28. न्यायालय ने यह भी पाया है कि इस त्रासदी के बारे में सूचना और रिपोर्ट पिछले 26 वर्षों से प्रसारित की जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की तारीख से वादी की अंतिम दोषसिद्धि तक, प्रेस के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने लगातार उक्त अपराध से संबंधित घटनाओं पर नजर रखी है और रिपोर्ट की है। यह सामग्री हमेशा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थी। वर्तमान कार्यवाही के संस्थापन से पहले, वादी ने न तो आरोप लगाया और न ही इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए उसका अधिकार प्रतिकूल था। इस प्रकार, इस न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय है कि प्रतिवादी सं. 4 और 5 का पुलिस परिसरों और न्यायालय परिसरों से अपनी त्रासद यात्रा का वर्णन करने का अधिकार वादी की कथित प्रतिष्ठा के अप्रमाणित नुकसान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

29. इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पुस्तक का प्रकाशन उस समय हुआ था जब पुनर्विचार याचिकाएं उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थीं। यह उस समय भी परिसंचरण में था जब उच्चतम न्यायालय ने अंततः पुनर्विचार याचिकाओं

को खारिज़ कर दिया था और जब वादी साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा था। वादी को 8 अक्टूबर 2021 को उस मामले में दोषी ठहराया गया था। उस स्तर पर भी उसने उपर्युक्त पुस्तक के संबंध में किसी व्यादेश राहत न मांगने का फैसला किया था । न्यायालय को 2016 में प्रकाशित किसी चीज के आधार पर अंतरिम व्यादेश की मंजूरी पर विचार करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता।

30. न्यायालय श्री अग्रवाल के इस कथन को स्वीकार करने में असमर्थ है कि चूंकि वेब सीरीज के व्यापक प्रसार और लिखित कार्य की तुलना में अधिक प्रभाव होने की संभावना है, इसलिए इस स्तर पर निषेधाज्ञा के अनुदान पर विचार किया जाना चाहिए। यह इसलिए कि वादी ने निष्क्रिय रहने का विकल्प चुना और पहले उपलब्ध अवसर पर कथित कार्य के संबंध में कोई पूर्व-निर्धारित कदम नहीं उठाए। न्यायालय ने पाया कि 2016 में लिखित और प्रकाशित पुस्तक के संबंध में व्यादेश राहत के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहने के बावजूद वादी को अंतरिम राहत देने का कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, अंतरिम या एकपक्षीय स्तर पर व्यादेश के अनुदान को आवश्यक रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए कि क्या वादी ने उचित तत्परता के साथ राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुना है। वादी का मामला इस आधार पर दुःखद रूप से विफल हो जाता है।

31. न्यायालय यह भी देखने के लिए विवश है कि प्रथमदृष्टया वादी ने स्पष्ट रूप से तात्विक तथ्यों को छिपाया है और गलत प्रस्तुतीकरण किया है, यह कहते हुए कि उसे 08 जनवरी 2023 को या उसके आसपास ही पुस्तक की सामग्री के बारे में पता चला था। वे खुलासे जो समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष दाखिल आवेदन में किए गए थे और जिनका उल्लेख श्री पाहवा स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि प्रतिवादियों 4 और 5 द्वारा लिखे गए कार्य को विशेष रूप से नोट किया गया था और लेख में संदर्भित किया गया था, जो तहलका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और कथित आवेदन के रिकॉर्ड का हिस्सा था । वादी को उक्त आवेदन दिया गया और 6 दिसंबर 2016 को जब इसका निपटान किया गया तो वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से भी उपस्थित हुआ। वास्तव में, और जैसा कि उस अवसर पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश से साबित होगा, वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बयान दिया कि वे पुनर्विचार याचिकाओं के निपटान तक भारत नहीं छोड़ेंगे। वादी सं. 4 और 5 द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में विधिवत अवगत होने के बावजूद, अज्ञात कारणों और उद्देश्यों के कारण वादी ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। प्रथमदृष्टया न्यायालय की राय है कि यह कहना कि उसे उक्त कार्य की सामग्री के बारे में केवल 08 जनवरी 2023 को पता चला, असंभव है।

32. न्यायालय अब इस बात पर विचार करने के लिए बाधित है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई पूर्व-प्रसारण व्यादेश मंजूर की जा सकती है । जैसा कि

खुशवंत सिंह की खण्ड पीठ ने ध्यान दिया था और कहा था, सूचना को प्रकाशित और प्रसारित करने के अधिकार को पवित्र माना जाना चाहिए। उस मामले के तथ्यों में यह पाया गया था कि पुस्तक की सामग्री, जिसके संबंध में एक निषेधाज्ञा मंजूर की गई थी और एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के संबंध में उसमें लगाए गए विभिन्न आरोप, सार्वजनिक डोमेन में थे और इस प्रकार वादी स्पष्ट रूप से किसी भी पूर्व-प्रकाशन निषेधाज्ञा की मंजूरी के लिए हकदार नहीं था। न्यायालय ने आगे कहा कि विभिन्न प्रकाशन, जिन्होंने घटनाओं का उल्लेख किया था और जिनका उल्लेख अपराध करने वाले कार्य में भी किया गया था, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं वह सामग्री जिसके संबंध में आपत्ति की गई थी, पहले से ही मौजूद थी और सार्वजनिक ज्ञान का विषय थी। इस प्रकार इस बात पर जोर दिया गया कि जबकि एक पूर्व प्रकाशन सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में योग्य नहीं हो सकता है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि क्या विषय वस्तु स्वयं सार्वजनिक डोमेन में थी। यहां प्राप्त तथ्यों पर पूर्वोक्त जाँच को लागू करने पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि लेखकों का वर्णन 2016 से ही सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध था। यह स्पष्ट रूप से वादी को अंतरिम राहत प्रदान करने से वंचित करता है।

33. लोक हित और प्रतिष्ठा के अधिकार, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा दावा किया जा सकता है, के संतुलन के बारे में विचार करते समय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि पूर्वोक्त पर विचार करते समय, मानहानि के लिए दावा

प्रकाशन को रोकने के लिए निवारक कार्रवाई से अधिक उपयुक्त होगा। **खुशवंत सिंह**, के मामले में खण्ड पीठ ने एक बार फिर वादी के उचित प्रेषण के साथ और पहले उपलब्ध अवसर पर न्यायालय में जाने की अनिवार्यता को दोहराया था।

34. न्यायालय ने नोट किया है कि प्रकाशन-पूर्व व्यादेश के मुद्दे पर विचार करते समय न्यायालय की खण्ड पीठ ने **खुशवंत सिंह** के सिद्धांतों को आधार बनाते हुए **पुष्प शर्मा बनाम डी. बी. कारपोरेशन और अन्य**[7] में यह मत व्यक्त किया था कि:

> **"21**. वादी की स्थिति कि बोनार्ड (उपरोक्त) सिद्धांत सभी परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब सामग्री, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट द्वारा प्रकाशित या प्रसारित किया जाना है, उसकी गहन जांच की आवश्यकता है। नई तकनीक निश्चित रूप से नई चुनौतियां पेश करती है। यह चुनौती अधिकारों को कमजोर करने के बजाय उन्हें संतुलित करने के लिए न्यायालय के कर्तव्य की आवश्यकता को उजागर करती है। डॉ. शशि थरूर (उपर्युक्त) ने इस पहलू पर सभी सुसंगत निर्णय विधि के आलोक में विचार किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया उच्च न्यायालय के ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बनाम ओ 'नील, 2006 एचसीए 46. बोनार्ड (ऊपर) सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और कनाडा में *कम्पास ग्रुप कनाडा (स्वास्थ्य सेवाएं)* लिमिटेड बनाम अस्पताल कर्मचारी संघ, 2004 बीसीएससी 128 एसीडब्ल्यूएस (3डी) 578 में कहा गया है कि कथित मानहानि को केवल असाधारण मामलों में, दुर्लभ और स्पष्ट मामलों में ही रोका जाना चाहिए और वादी पर दबाव है कि वह यह प्रदर्श करे कि सामग्री संबंधी शिकायत स्पष्ट रूप से मानहानिकारक थी और इसके विपरीत कोई भी फैसला न्यायालय द्वारा विकृत माना जाएगा। बाद में *हचेन्स बनाम एसडब्ल्यूसीए एम. कॉम*, 2011 ओएनएससी 56 में भी इस बात पर जोर दिया गया था कि वादी को प्रदर्शित आदेश में अंतवर्ती राहत प्राप्त करने के लिए समर्थ, योग्य होना चाहिए- ताकि जब प्रतिवादी को मौका दिया जाएगा

तो वह इस भाषण की सामग्री को उचित ठहराने के लिए अधिरोपित आदेश में असमर्थ होगा।

22. निसंदेह, नए युग का मीडिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट बड़ी चुनौतियां पैदा करता है। उनके अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुमूल्य अधिकार को कम नहीं किया जाना चाहिए, जो, यदि ऐसा कहा जा सकता है तो, लोकतंत्र की जान है। स्वतंत्र भाषण से संबंधित मुद्दों में हितकारी और स्थापित सिद्धांत यह है कि सार्वजनिक हस्तियों और सार्वजनिक संस्थानों को कथित मानहानि या मानहानि के संबंध में व्यादेश राहत प्राप्त करने के लिए बहुत ही उच्च सीमा तक पहुँचना होगा [आर. राजगोपाल (उपरोक्त)]। *करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य*, 1956 एस. सी. आर. 476 मामले में दिया गया निर्णय भी इस बात को रेखांकित करता है कि "वे लोग जो जन सामान्य के बीच काम करते हैं, उन्हें अपने बारे में कही जाने वाली बातों के मामले में अत्यंत संवेदनशील नहीं होना चाहिए"। इस न्यायालय की यह भी राय है कि केवल स्थायी व्यादेश की राहत सिद्धांत को नहीं बदलती है। जिस वाद हेतुक पर मुक़दमी अपने मुकदमा को आधारित करते हैं, वह कथित मानहानि है। अतः एकपक्षीय स्तर पर व्यादेश राहत के सामान्य सिद्धांत, विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् वाणी पर नियंत्रण, समान होंगे। अन्य व्याख्या का अर्थ यह होगा कि वादी केवल अलग राहत का दावा करने और यह तर्क देने के उपकरण द्वारा कि यदि इनकार किया गया तो मुकदमा हार जाएगा, शासी सिद्धांतों को तब्दीली कर सकता है। यह असामान्य नहीं है कि स्थायी व्यादेश के मुकदमे में, वादी अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने में असमर्थ है। यह स्वयं वादी को, यदि अन्यथा हकदार है भी तो किसी राहत के लिए हकदार नहीं बनाएगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में क्या साबित हुआ है।

23. ह म महसूस करते हैं कि यह कहने के सिवाय और कुछ जोड़ना उचित नहीं होगा कि जब कभी जिस प्रकार कीअंतर्वर्ती या एक पक्षीय व्यादेश राहत, जिससे यह न्यायालय संबंधित है, की मांग की गई, प्रथमदृष्टया रूप

> से उच्च स्तर का होना चाहिए। इस प्रकार, स्थापित नियम और सिद्धांत पर विचार के परिणाम स्वरूप न्यायालय अपने आदेशों से सार्वजनिक बहस को दबाएगी। इस देश की जनता और नागरिक इस बारे में समाचार और निष्पक्ष टिप्पणी की उम्मीद करते हैं कि क्या कोई सार्वजनिक संस्थान- मीडिया हाउस या जर्नल (जो सार्वजनिक संस्थान होने के कारण अपवाद नहीं बन सकते क्योंकि वे एक माध्यम है जिसके द्वारा सूचना का प्रसार किया जाता है और लोकतंत्र के स्तंभों में से एक हैं) ठीक से काम करता है। यदि ऐसे आरोप हैं जो कि विवादों को बढ़ावा देते हैं, जो कि एक या अन्य समाज में समाचार का प्रसार करता है, लोक विवाद का विषय है। जब तक की शुरुआत से ही यह दिखाया न जाए कि आपत्तिजनक अंतर्वस्तु अप्रिय या स्पष्ट रूप से झूठ है, निषेधाज्ञा, वह भी एक पक्षीय, बिना किसी कारण को अभिलेखित किये नहीं दी जानी चाहिए। लोकतंत्र बहस में मजबूती की अपेक्षा रखता है, जो कि अक्सर लोकप्रिय हस्ती और लोक संस्थान- जैसे कि मीडिया हाउसेस, जर्नल और संपादकों को सुर्ख़ियों में लाता है। यदि न्यायालय समय समय पर बहस को दबाए, जो कुछ भी राज्य द्वारा कानून के माध्यम से जो नहीं किया जा सकता, उसे सटीक संवैधानिक मानकों को पूरा किए बिना अप्रत्यक्ष रूप से हासिल किया जा सकता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यवान अधिकार के उल्लंघन की अनुमति देते हैं।

35. **पुष्प शर्मा** ने उच्च सीमा के सिद्धांत को दोहराया था जिसे प्रकाशन-पूर्व व्यादेश जारी करने के औचित्य पर विचार करते समय पूरा किया जाना चाहिए। यह माना गया था कि जब तक शुरुआत में यह स्थापित नहीं किया जाता है कि उल्लंघन करने वाली सामग्री दुर्भावनापूर्ण और स्पष्ट रूप से झूठी है, तब तक निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि इसमें ऊपर बताया गया है कि यह प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है क्योंकि वेब सीरीज की सामग्री को पूरी तरह से देखा और मूल्यांकन किया जाना बाकी है। न्यायालय ने यह नोट किया कि **पुष्प**

शर्मा में विद्वान न्यायाधीशों ने **बोनार्ड बनाम पैरीमैन**[8] सिद्धांत का उल्लेख किया था जिसका अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा लगातार पालन किया गया है।

36. **हॉली बनाम स्मिथ**[9], मामले में, लार्ड जस्टिस ऑल्ड और स्लेड के माध्यम से अपील न्यायालय को उन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझने का अवसर मिला जो प्रकाशन-पूर्व व्यादेश की मंजूरी को नियंत्रित करते हैं और अभिनिर्धारित करते हैं :

"*बोनार्ड बनाम पेरीमैन नियम*

> क्योंकि मानहानि अधिनियम 1792 (फॉक्स अधिनियम) के बाद से यह प्रश्न कि मानहानि या नहीं' और क्या किसी मानहानि को उचित या विशेषाधिकार प्राप्त है, न्यायपीठ की जिम्मेदारी रही है (अधिनियम के पहले प्रकाशन का तथ्य और अटकलों की सच्चाई जूरी के लिए प्रश्न थे)। अंतवर्ती प्रक्रम पर उस उत्तरदायित्व पर न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना को और 60 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश लार्ड कोलरिज ने *बोनार्ड बनाम पैरीमैन* [1891] 2 सीएच 269,281 [1891-4] में इंगित किया था कि 968 पर ऑल ईआर रिप 965, 1854 में कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट के अधिनियम तक कॉमन लॉ कोर्ट ने व्यादेश राहत प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं की थी। न्याय परस्त न्यायालय अभी भी ऐसा नहीं कर सकीं क्योंकि उनके पास मानहानि के मामलों में फैसला करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ जुडिकेचर एक्ट, 1873 तक इंतजार करना पड़ा, जब वे उच्च न्यायालय का चांसरी डिवीजन बन गए और इस प्रकार

उन्हें मानहानि के क्षेत्र में और साथ ही साथ अपकृत्य के अन्य कार्यों में अपनी पारंपरिक व्यादेश भूमिका का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई। मानहानि के मामलों में अंतवर्ती राहत प्रदान करने की अपनी शक्ति पर न्यायालयों के विचार के शुरुआती दिनों से वे दो संबद्ध विचारों से निर्देशित प्रतीत होते हैं, एक उच्च सिद्धांत का और दूसरा सिद्धांत और व्यावहारिकता का। पहले व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा का महत्व है। दूसरा यह अभिस्वीकृति है कि न्यायाधीशों को, स्पष्ट मामले को छोड़कर, किसी कथन के अंतर्वर्ती चरण के प्रकाशन पर रोक लगाकर जूरी की भूमिका नहीं लेनी चाहिए, जो बाद में जूरी को कोई मानहानि या सत्य या अन्यथा प्रतिरक्षणीय नहीं मिल सकता है। कभी-कभी दूसरी धारणा इस रूप में व्यक्त की जाती है कि किसी न्यायाधीश को अंतवर्ती चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके समक्ष साक्ष्य इतनी स्पष्ट रूप से एक आपराधिक मानहानि को स्थापित नहीं करता है कि उसे विश्वास है कि उसे जूरी के विपरीत निर्णय को विकृत के रूप में दरकिनार करना होगा।

समस्या पर विचार किए जाने से बहुत पहले *इंग्लैंड के कानूनों पर अपनी टिप्पणियां* में उन धारणाओं में से पहली के लिए निम्नलिखित लहजे में दृश्य सेट किया, एक जो बाद के वर्षों में, कम से कम प्रेस के खिलाफ मानहानि कार्यों में अंतरिम निषेधाज्ञा की मंजूरी का मार्गदर्शन करना थाः

"इस मामले में और अन्य उदाहरण जिन पर हमने हाल ही में विचार किया है, जहाँ ईशनिंदा, अनैतिक, राजद्रोही, विभाजनकारी, राजद्रोही या

अपमानजनक टिप्पणियों को अंग्रेजी कानून द्वारा दंडित किया जाता है, कुछ को अधिक से अधिक, दूसरों को कम से कम गंभीरता के साथ प्रेस की स्वतंत्रता को, ठीक से समझा जाए, किसी भी तरह से उल्लंघन या उल्लंघन नहीं किया जाता है।" प्रेस की स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्र राज्य की प्रकृति के लिए आवश्यक है, लेकिन इसमें प्रकाशन पर कोई पूर्व प्रतिबंध नहीं है, और जब प्रकाशित होता है तो आपराधिक मामले के लिए परिनिंदा से स्वतंत्रता नहीं है। प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति को जनता के समक्ष अपनी भावनाएं रखने का निःसंदेह अधिकार हैः इसे रोकना, प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करना हैः लेकिन अगर वह अनुचित, शरारतपूर्ण या अवैध का प्रकाशन करता है, तो उसे अपने ही दुस्साहस का परिणाम भुगतना होगा। प्रेस को एक लाइसेंसधारक की प्रतिबंधात्मक शक्ति के अधीन करना, जैसा कि पहले किया गया था, क्रांति से पहले और उसके बाद से, सभी प्रकार की भावनाओं की स्वतंत्रता को एक व्यक्ति के पूर्वाग्रहों के अधीन करना है, और उसे सीखने, धर्म और सरकार के सभी विवादित बिंदुओं का मनमाना और त्रुटिहीन न्यायाधीश बनाना है। लेकिन किसी भी खतरनाक या आपत्तिजनक लेखन को दंडित करने के लिए (जैसा कि वर्तमान में कानून करता है), जो प्रकाशित होने पर निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई के आधार पर हानिकारक प्रवृत्ति के रूप में घोषित किया जाएगा, शांति और अच्छी आदेश, सरकार और धर्म, नागरिक स्वतंत्रता की एकमात्र मजबूत नींव के संरक्षण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार व्यक्तियों की इच्छा अभी भी स्वतंत्र है- केवल उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग, दुरुपयोग करना कानूनी दंड का उद्देश्य है। (देखें 4 बीएल कॉम (1854 संस्करण) 182-183)।

न्यायशास्त्र का प्रारंभिक बिन्दु *बोनार्ड बनाम पैरीमैन* के पूर्व विनिश्चय में लार्ड एशर एमआर के निर्णय का एक अंश है, अर्थात् कॉल्सन बनाम कॉल्सन (1887) 3 टीएलआर 846 में 846:

'... मानहानि या ना मानहानि का सवाल जूरी के लिए था। यह जूरी का काम था और न्यायालय का काम नहीं था कि वह दस्तावेज का अर्थ लगाए और कहे कि यह मानहानि है या नहीं। अंतरिम व्यादेश देने में न्यायालय को न्यायोचित ठहराने के लिए जूरी द्वारा यह निर्णय लेने से पहले कि यह मानहानि है या नहीं, मानहानि के प्रश्न पर निर्णय लेना चाहिए। इसलिए, अधिकार क्षेत्र नाजुक प्रकृति का था। इसका प्रयोग केवल स्पष्ट मामलों में किया जाना चाहिए, जहां कोई भी जूरी यह कहेगी कि जिस मामले की शिकायत की गई है वह निंदनीय है, और जहां, यदि जूरी ने ऐसा नहीं पाया, तो न्यायालय निर्णय को अतार्किक के रूप में रद्द कर देगा। न्यायालय को इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिए कि सभी संभावनाओं में कथित मानहानि असत्य थी, और यदि किसी विशेषाधिकार प्राप्त अवसर पर लिखा गया था कि प्रतिवादी की ओर दुर्भावना थी। यह उन तीन नियमों का पालन करता है कि न्यायालय केवल विरले अवसरों पर ही अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।" (क्वार्ट्ज हिल कंसोलिडेटेड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम बील भी देखें) (1882) 20 सीएच डी 501 प्रति जेसेल एमआर पर 508) मामले में मुख्य मुद्दा यह प्रतीत होता है कि क्या धमकी वाला प्रकाशन निंदनीय था, लेकिन आरोप की सच्चाई के बारे में एक स्पष्ट मुद्दा भी था, और लॉर्ड एशर एमआर द्वारा औचित्य और विशेषाधिकार के साथ-साथ मानहानि या कोई मानहानि के मुद्दों के संदर्भ से पता चलता है कि उनका इरादा उन सभी मामलों पर लागू होने का था जो अंततः जूरी के प्रांत के भीतर थे। लिंडले एल. जे. ने एक संक्षिप्त समनुरूप निर्णय में लगभग वही कहा (1887) 3 टी. एल. आर. 846 847 पर) मास्टर ऑफ द रोल्स द्वारा निर्धारित नियमों से

सहमत थे, और वह यह कहने के लिए तैयार नहीं थे कि अधिकार क्षेत्र के अनुसार यह मानहानि नहीं थी, या यह कथित मानहानि सच थी।'

मुख्य न्यायाधीश लार्ड कोलरिज ने *बोनार्ड बनाम पैरीमैन* मामले में पूर्ण अपील न्यायालय का अग्रणी निर्णय सुनाते हुए उस मामले में अंतर्वर्ती अवरोध को समाप्त करने के पक्ष में लार्ड एशर एमआर और लिंडले, बोवेन और लोप्स एलजेजे से सहमति व्यक्त की और *कॉलसन बनाम कॉलसन* मामले में लार्ड एशर एमआर के उन शब्दों को दोहराया और अपनाया। उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि असाधारण मामलों को छोड़कर सभी मामलों में (देखिए [1891] 2 अध्याय 269 285, [1891-4] ऑल ईआर रिप्रेजेंटेशन 965 at 969) न्यायालयों को अंतवर्ती राहत के माध्यम से ऐसे मानहानि के प्रकाशन पर रोक नहीं लगानी चाहिए जिसे बचाव पक्ष ने वहां न्यायोचित ठहराने की कोशिश की जहां यह स्पष्ट था कि प्रतिरक्षा विफल हो जाएगी। उन्होंने मानहानि के मामलों में विशेष आवश्यकता के आधार पर यह दृष्टिकोण अपनाया कि जूरी द्वारा मामले के अंतिम निर्धारण से पहले हस्तक्षेप करके, असत्य मानहानि के स्पष्ट मामले को छोड़कर, स्वतंत्र भाषण के अधिकार को प्रतिबंधित न किया जाए। उन्होंने कहा हैः

"मानहानि के लिए किसी कार्रवाई की विषय-वस्तु इतनी विशेष है कि किसी प्रत्याशित गलती को रोकने के लिए किसी कार्रवाई के विचारण से पूर्व व्यादेश द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में असाधारण चेतावनी अपेक्षित है।" अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वह है जो लोगों के हित में होना चाहिए और वास्तव में उन्हें बिना किसी बाधा के काम

करना चाहिए, जब तक कोई गलत कार्य नहीं किया जाता है और जब तक कोई कथित मानहानि असत्य नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन इसके विपरीत, अक्सर किसी कथित मानहानि के प्रकाशन और पुनरावृत्ति में बहुत ही हितकर कार्य किया जाता है। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि कथित मानहानि असत्य है, तब तक यह स्पष्ट नहीं है कि किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया गया है और मानहानि के मामलों में बोलने की स्वतंत्रता को बेरोक-टोक छोड़ने का महत्व एक मजबूत कारण है जो अंतरिम व्यादेशों को मंजूरी देने के साथ सबसे सावधानी और सतर्कता से व्यवहार करता है... हमारे सामने विशेष मामले में, वास्तव में, प्रकाशन का अपमानजनक चरित्र विवाद से परे है, लेकिन प्रतिवादी पर इसके प्रभाव का निपटान करना केवल जूरी द्वारा ही किया जा सकता है"

हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि औचित्य की प्रतिरक्षा वह है जो तथ्यों के आधार पर, जो उनके सामने हो सकता है, जूरी को पूरी तरह से निराधार हो सकता है और न ही हम यह बता सकते हैं कि नुकसान की भरपाई क्या हो सकती है।(देखें [1891] 2 सीएच 269 284 पर, [1891-4] ऑल ईआर रेप 965 968 पर। न्यायालय के शेष सदस्य के. एल. जे. ने इस सामान्य प्रतिपादना से सहमति व्यक्त की (देखिए [1891] 269 पर 285, [1891-4] ऑल ई. आर. रेप 965 पर 969) किंतु तीन आधारों पर अंतवर्ती व्यादेश को समाप्त करने के न्यायालय के निर्णय से असहमति प्रकट कीःपहला, कथित मानहानि को इस तरह से व्यक्त किया गया था कि यह सुझाव दिया गया था कि यह जनता के हितों की रक्षा हेतुक के बजाय जनता के हितों की रक्षा हेतुक के लिए प्रेरित था, दूसरा, प्रतिवादी इस

साक्ष्य पर कि मानहानि असत्य थी, एक मजबूत प्रथमदृष्टया मामले का खंडन हेतुक में विफल रहा था और तीसरा, सुविधा और असुविधा का अतिशेष ; संतुलन अस्थायी संयम जारी रखने के पक्ष में था क्योंकि इससे प्रतिवादी को कथित मानहानि को प्रकाशित नहीं हेतुक में थोड़ा नुकसान होगा और विचारण के परिणाम के लंबित रहने तक वादी को बहुत नुकसान होगा। इनमें से पहला और तीसरा आधार तब से बोनार्ड बनाम पेरीमैन नियम के बहुमत के तर्क या न्यायालयों के आवेदन से मेल नहीं खाता है। मॉनसन बनाम मैडम तुसाद लिमिटेड [1894] 1 क्यूबी 671, [1891-4]

ऑल ईआर रेप 1051 एक ऐसा मामला था जिसमें दोनों मुद्दे थे कि क्या अपमानजनक सामग्री अपमानजनक थी और क्या प्रतिवादी ने किसी भी घटना में इसके प्रकाशन के लिए सहमति व्यक्त की थी। न्यायालय के सदस्यों (लार्ड हाल्सबरी और लोप्स और डेवी एल जे) ने अंतवर्ती राहत से इंकार करते हुए पहले मुद्दे पर न्यायालय के उचित दृष्टिकोण के बारे में मतभेद व्यक्त किया, लेकिन सभी ने बोनार्ड बनाम पेरीमैन नियम को भुनाया कि इस तरह की राहत केवल अपवादस्वरूप मानहानि के मामले में उपयुक्त थी जिसका स्पष्ट रूप से कोई बचाव नहीं था।हाल के अधिकारी इस नियम की ताकत को स्वीकार करते हैं और इसके दो संबद्ध कारणों को स्पष्ट करते हैं, जिनका उल्लेख मैंने किया है, हालांकि प्रत्येक को हमेशा समान सापेक्ष महत्व नहीं देते हैं।

फ्रेजर बनाम इवांस [1969] 1 ऑल ईआर 8 एट 10, [1969] 1 क्यूबी 349 एट 360-361 में लार्ड डेनिंग एमआर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रमुखता दीः

'न्यायालय किसी लेख के प्रकाशन पर रोक नहीं लगाएगा, भले ही वह मानहानिकारक हो, जब प्रतिवादी कहता है कि वह इसे उचित ठहराना चाहता है या सार्वजनिक हित के किसी मामले पर उचित टिप्पणी करना चाहता है।यह बोनार्ड बनाम पेरीमैन ([1891] 2 सीएच 269, [1891-4] ऑल ईआर रेप 965) के बाद से कई वर्षों से स्थापित किया गया है। कभी-कभी इसका कारण यह दिया जाता है कि औचित्य और निष्पक्ष टिप्पणी की प्रतिरक्षा जूरी के लिए होती है, जो संवैधानिक न्यायाधिकरण है, न कि न्यायाधीश के लिए कारण यह है कि जनहित में सच्चाई का महत्व है। यदि यह [कथित मानहानि] सही है, या जनहित के किसी मामले पर उचित टिप्पणी है तो कोई गलत काम नहीं किया गया है। न्यायालय प्रकाशन के पूर्व व्यादेश मंजूर करके मुद्दे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।"

इसी प्रकार के प्रभाव के लिए, यद्यपि एक अन्य संदर्भ में (अर्थात् व्यतीत किए गए 'दोषसिद्धियों' के प्रकाशन के औचित्य की प्रतिरक्षा के भाग के रूप में विद्वेष की कमी का मुद्दा-देखिए अपराधियों का पुनर्वास अधिनियम, 1974 की धारा 4 (1) और 8 (5) हर्बेज बनाम प्रेसड्रेम लिमिटेड (1984) 2 ऑल ईआर 769, (1984) 1 डब्ल्यूएलआर 1160 एट 1162 में ग्रिफिथ एलजे के निर्णय से निम्नलिखित अंश है जब मानहानि कार्यों में अंतरिम व्यादेशों की मंजूरी को सामान्यतया लागू अनेक सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया जाता हैः

'...यदि प्रतिवादी औचित्य की प्रतिरक्षा करता है तो कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा।यह एक ऐसा नियम है जो इतनी अच्छी तरह से स्थापित है

कि प्राधिकरण के विस्तृत उद्धरण की आवश्यकता नहीं है।यह बोनार्ड बनाम पेरिमैन के प्रमुख मामले से पता लगाया जा सकता है... ये सिद्धांत अदालत द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दिए गए मूल्य के कारण विकसित हुए हैं और मैं प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी सोचता हूं, जब इसे एक एकल व्यक्ति की प्रतिष्ठा के खिलाफ संतुलित किया जाता है, जिसे, यदि गलत है, तो नुकसान में मुआवजा दिया जा सकता है।'

आधुनिक अधिकारी

तुलनात्मक रूप से हाल ही में कई ऐसे प्राधिकारी हैं जिनमें न्यायालयों ने बोनार्ड बनाम पेरिमैन के सामान्य नियम के अपवाद के रूप में वादी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से धमकी भरी मानहानि पर रोक लगाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है और प्रतिवादी पर किसी दावे के गलत होने पर क्षतिपूर्ति करने के लिए उस पर दबाव डालने के साधन के रूप में ऐसा किया गया है।

क्रेस्ट होम्स लिमिटेड बनाम एस्कॉट [1980] एफएसआर 369 मामले में, इस अदालत ने 1975 में एक निर्णय दिया था, लेकिन केवल 1980 में रिपोर्ट किया, एक असंतुष्ट खरीदार ने बिल्डर से मुआवजे की असफल मांग की थी, और मुआवजा देने के लिए उस पर दबाव डालने की दृष्टि से मानहानि की धमकी दी थी। अदालत ने पहली बार मानहानि पर रोक लगाने के लिए दी गई एक अंतवर्ती निषेधाज्ञा को समाप्त कर दिया। लार्ड डेनिंग एमआर, जिनके साथ स्टीफनसन और जेफ्री लेन एलजेजे सहमत थे, ने यह अभिनिर्धारित किया कि *बोनार्ड बनाम पैरीमैन* द्वारा स्थापित

सामान्य नियम के बाहर मामले को ले जाने के लिए न तो धमकी वाले मानहानि का अनुचित तरीका और न ही इसके लिए आर्थिक उद्देश्य पर्याप्त था।जेफ्री लेन एलजे ने अपने संक्षिप्त सर्वसम्मत निर्णय में उस सामान्य नियम की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा (399 पर):

'....प्राधिकारियों की लाइन लम्बी और महत्वपूर्ण है कि इन मामलों में अंतवर्ती व्यादेश मंजूर नहीं किए जाएंगे....'

जब तक वादी यह न दिखाए कि औचित्य की प्रतिरक्षा सफल नहीं होगी। और उन्होंने इस विचार के बावजूद नियम लागू किया कि प्रतिवादी ने अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक अश्लील और आक्रामक तरीका चुना था और यह कि वादियों को होने वाला नुकसान व्यापक और स्पष्ट रूप से साबित करना मुश्किल था।

बेस्टोबेल पेंट्स लिमिटेड बनाम बिग [1975] एफएसआर 421 में ओलिवर जे, क्रेस्ट होम्स मामले के बाद, पेंट के असंतुष्ट खरीदार को रोकने से इनकार कर दिया, जिसने विक्रेता से मुआवजा प्राप्त करने की दृष्टि से, इसे मानहानि करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यह तथ्य कि खरीदार दुर्भावनापूर्ण हो सकता है या उसका उद्देश्य विक्रेता पर अपने दावे को निपटाने के लिए दबाव डालना था, अप्रासंगिक है (434-436 पर देखें)।

अंत में, अल फयेद बनाम द ऑब्जर्वर लिमिटेड (1986) टाइम्स, 14 जुलाई न्यायमूर्ति मान ने सामान्य नियम के एक अपवाद के रूप में मानने से इनकार कर दिया और कहा कि द ऑब्जर्वर ने हैरोड्स लिमिटेड के नियंत्रण के लिए एक वाणिज्यिक प्रतिद्वंदी द्वारा एक प्रतिशोध के रूप में

उनके खिलाफ लगातार और गैर जिम्मेदाराना अभियान चलाकर अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग किया था। उन्होंने, प्राधिकारियों की समीक्षा करने के बाद, अभिनिर्धारित किया कि सामान्य सिद्धांत का एकमात्र अपवाद वह है जहां आरोप स्पष्ट रूप से असत्य है और यह कि यह धमकी भरे प्रकाशन के लिए कोई भी उद्देश्य या कारण हो, लागू होता है, मुझे कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 पर भी विचार करना चाहिए। यह उपलब्ध कराता है, जहां तक सामग्री हैः

प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में सूचना देने एवं प्रदान करने का अधिकार सम्मिलित है |

"(2) इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग, क्योंकि इसके साथ कर्तव्य और उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं, ऐसी औपचारिकताओं, शर्तों, प्रतिबंधों या शास्तियों के अधीन हो सकते हैं जो कानून द्वारा विहित हैं और एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक हैं,... अपराध की रोकथाम के लिए,... दूसरों की प्रतिष्ठा या अधिकारों की रक्षा के लिए..." ए-जी बनाम गार्जियन न्यूजपेपर्स लिमिटेड (संख्या 2) [1988] 3 ऑल ईआर 545 में 660-661, [1990] 1 एसी 109 पर 283-284 पर लॉर्ड गोफ ने कहा कि अनुच्छेद 10 अंग्रेजी कानून के अनुरूप है और जब बाद में अनुमति दी जाती है तो उसे अंग्रेजी कानून के निर्वचन का मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने अनुच्छेद में स्वतंत्र रूप से बोलने के अधिकार पर प्रतिबंधों का उल्लेख किया, जिसमें कानून द्वारा विहित और... लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक 'शामिल हैं, और कहा ([1988] 3 ऑल ईआर 545 660,[1990] 1 एसी 109 283):

"यह मानव अधिकारों के यूरोपीय न्यायालय के न्यायशास्त्र में स्थापित किया गया है कि इस संदर्भ में" "आवश्यक उपाय "शब्द का अर्थ एक अत्यावश्यक सामाजिक आवश्यकता का अस्तित्व है, और यह कि" ""

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए जाने वाले वैध लक्ष्य के अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए। मेरे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अंग्रेजी कानून, जैसा कि अदालतों में लागू होता है, किसी भी अलग निष्कर्ष पर पहुंचता है।"

मानव अधिकारों के यूरोपीय न्यायालय के न्यायशास्त्र से व्युत्पन्न 'सामाजिक आवश्यकता' और आनुपातिकता के मानदंड, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सामान्य अधिकार के किसी अपवाद के लिए, पिछले सौ वर्षों में अंग्रेजी अदालतों के बोनार्ड बनाम पेरिमैन नियम के कठोर अनुप्रयोग के तर्क के साथ एक टुकड़ा है (देखें द ऑब्जर्वर बनाम यूके (1991) 14 ईएचआरआर 153 एट 191 (पैरा 59) जहां यह कहा गया था कि अपवादों की संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए और किसी भी प्रतिबंध की आवश्यकता को आश्वस्त रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। थोरगर्सन बनाम आइसलैंड (1992) 14 ईएचआरआर 843, पृ. 865 (पैरा 63) भी देखिए। हॉफमैन एलजे ने हाल ही में एक अलग संदर्भ में इस सिद्धांत के महत्व को रेखांकित किया है

आर बनाम सेंट्रल इंडिपेंडेंट टेलीविजन पीएलसी [1994] 3 ऑल ईआर 641 में 651-652, [1994] फैम 192 at 202-203: "वे उद्देश्य जो न्यायाधीशों को अन्य हितों के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करने की शक्ति ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके समक्ष विअतिशेष ;

संतुलन मामले के तथ्यों के आधार पर लगभग हमेशा समझ में आने वाले और मानवीय होते हैं।" ""समाचार पत्र कभी-कभी गैर-जिम्मेदाराना होते हैं और बाजार अर्थव्यवस्था में उनके उद्देश्यों को वाणिज्यिक लाभ के विचारों से अलग नहीं किया जा सकता है। और प्रहेतुक शन व्यक्तियों को अनावश्यक पीड़ा, संकट और क्षति या जनहित के अन्य पहलुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एक स्वतंत्रता जो न्यायाधीशों के लिए उत्तरदायी या जनहित में सोचने तक सीमित है, वह स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है उन चीजों को प्रकाशित करने का अधिकार जो सरकार और न्यायाधीश, चाहे वे कितने ही अच्छे इरादे से क्यों न हों, सोचते हैं कि प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए। इसका अर्थ है ऐसी बातें कहने का अधिकार जो सही सोच वाले लोग खतरनाक या गैरजिम्मेदाराना मानते हैं।यह स्वतंत्रता केवल सामान्य अधिनियम या अधिनियम द्वारा निर्धारित स्पष्ट रूप से परिभाषित अपवादों के अधीन है। इसके अलावा, कन्वेंशन के तहत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा आदेश में हमें सक्षम बनाने के लिए... यह आवश्यक है कि कोई भी अपवाद अनुच्छेद 10 (2) में निर्धारित परीक्षाओं को पूरा करे। इस बात पर जोर नहीं दिया जा सकता कि स्थापित अपवादों (या ऐसे किसी नए अपवादों, जिन्हें संसद कन्वेंशन के अधीन अपने दायित्वों के अनुसार अधिनियमित कर सकती है) के बाहर अन्य हितों के साथ अभिव्यक्ति निश्चित स्वतंत्रता के संतुलन का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो हमेशा जीतता है।"

प्राधिकार की अनुपस्थिति में में भी, मैं यह निर्णय देने के लिए तैयार हूं कि ऐसे मामले में जहां कोई प्रतिवादी सूचना प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखता है, जिसका वह दावा करता है कि वह औचित्य सिद्ध कर सकता है, न्यायालय

को बोनार्ड बनाम पेरीमैन के नियम से केवल इसलिए नहीं हटना चाहिए क्योंकि वह प्रस्तावित प्रकाशन में उसके उद्देश्यों को दुनिया को सच्चाई बताने की शुद्ध इच्छा से कम ऊंचा मानती है। कई मामलों में, शायद अधिकांश मामलों में, आशयित प्रकाशन के उद्देश्य मिश्रित हो सकते हैं और उद्देश्य की जांच, विशेष रूप से एक अंतर्वर्ती अनुप्रयोग पर, कुछ हद तक अटकलबाजी हो सकती है।सामान्य कानून के तहत प्रतिवादी के इरादे आमतौर पर उसे कानूनी अधिकार का उपयोग करने से रोकने के लिए पर्याप्त आधार नहीं देते हैं।

तथापि, मेरी राय में, ऑल्ड एल जे द्वारा उद्धृत प्राधिकारी स्वयं यह स्थापित करते हैं कि न तो परिवादी का आशय और न ही जिस रीति से वह प्रकाशन के लिए धमकी देता है और न ही वादी को संभावित क्षति सामान्य रूप से नियम का अपवाद बनाने का आधार है। मैं इनमें से तीन प्राधिकरणों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

बोनार्ड बनाम पैरीमैन के मामले में न्यायमूर्ति के. एल. जे. ने अपने विसम्मत निर्णय ([1891] 2 सीएच 269 at 285) में इंगित किया था कि कथित मानहानि असभ्य और गाली-गलौज की भाषा में व्यक्त की गई थी, जो इसे पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति इस विश्वास में झुक जाएगा कि वादियों के खिलाफ घृणा या दुर्भावना की कोई व्यक्तिगत भावना थी, न कि केवल जनता के हितों की रक्षा करने की इच्छा प्रतिवादी के वास्तविक उद्देश्यों में थी।"

बेस्टोबेल पेंट्स लिमिटेड बनाम बिग [1975] एफएसआर 421 में इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्रतिवादी की धमकी वादी पर अपने दावे को निपटाने के लिए दबाव डालने के लिए थी, वास्तव में वादी के वकील ने धमकी को

'ब्लैकमेल' के रूप में वर्णित किया (हालांकि निर्णय (424 पर) यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान मामले की तरह, उस विवरण की सटीकता या अन्यथा का तर्क में परीक्षण नहीं किया गया था)। फिर भी न्यायमूर्ति ओलिवर ने अंतवर्ती राहत देने से इंकार कर दिया। प्राधिकारियों की व्यापक समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा (434 पर):

जहां तक मैं जानता हूं, यह कभी सुझाव नहीं दिया गया है कि मानहानि के सामान्य मामले में, यह अनुदान या अंतवर्ती राहत को रोकने में कोई अंतर पैदा करता है कि मानहानिकारक बयान दुर्भावनापूर्ण रूप से प्रकाशित किया गया है."

क्रेस्ट होम्स लिमिटेड बनाम एस्कॉट [1980] एफएसआर 396 में अपील न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि प्रासंगिक बयान वादियों को उनके व्यवसाय में नुकसान पहुंचाने के लिए परिकलित किया गया था और प्रतिवादियों के मुआवजे के दावे को निपटाने के लिए उन पर दबाव डालने की दृष्टि से बोनार्ड बनाम पेरीमैन में मामले को नियम से बाहर ले जाया गया था। लार्ड डेनिंग एमआर ने स्पष्ट रूप से कहा (398 पर):

बाद में [वादियों के वकील] ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि [वादी] मुआवजा दे सकें। प्रतिवादी को कार्रवाई करनी चाहिए थी और उस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। यह ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी इस मामले को सामान्य नियम से बाहर निकालना पर्याप्त नहीं है।"

मैं यह प्रतिग्रहण करना, प्रतिगृहीत करना, स्वीकार करना करता हूं कि अपवादात्मक परिस्थितियों में बोनार्ड बनाम पैरीमैन मामले में नियम लागू करने से इनकार करने का विवेकाधिकार अदालत के पास रह सकता है। एक अपवाद, जिसे उस निर्णय में ही स्वीकार किया गया है, वह वह मामला है जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मानहानिकारक बयान स्पष्ट रूप से असत्य है.तथापि, मेरे विचार से यह एक विवेकाधिकार है जिसका प्रयोग स्थापित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। मेरे निर्णय में न्यायमूर्ति इयान केनेडी ने वर्तमान मामले में प्रतिवादी के अनुमानित उद्देश्यों के संबंध में स्थापित सिद्धांतों के विपरीत कार्य किया, जो नियम को लागू करने से अपने इनकार को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त असाधारण परिस्थितियों का गठन करता है|

37. **बोनार्ड** सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने नोट किया कि प्रतिवादियों से अब तक सत्य या औचित्य का अभिवचन करने के लिए नहीं कहा गया है। औचित्य की कसौटी यह है कि अदल-बदल हो सकता है और अदल-बदल नहीं हो सकता। न्यायालय ने आगे **आर बनाम भारत संघ** मामले में दर्ज गर्भवती टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा।

सेंट्रल इंडिपेंडेंट टेलीविजन[10] [एक निर्णय जो ध्यान में आया

होली में अनुमोदन के साथ) कि स्वतंत्रता में वह भी प्रकाशित करने का अधिकार शामिल है जो सरकार और न्यायाधीश, चाहे वे कितने ही अच्छे इरादे से क्यों न हों, इसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए।"

तदनुसार, और उपरोक्त कारणों से, अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप आवेदन इस चरण में खारिज कर दिया जाएगा।

यशवंत वर्मा, न्यायाधीश

12 जनवरी, 2023/ एसयू/आरएसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*